श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

DoIT

राजस्थान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन

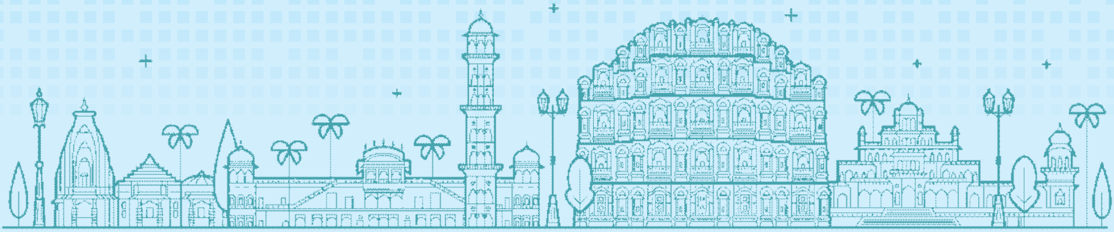

Ashok Gehlot
Chief Minister, Rajasthan

Our great leader former Prime Minister Bharat Ratna late Shri Rajiv Gandhi Ji long back realised the power and importance of Information Technology and introduced computers in India on a large scale. As a result of Shri Rajiv Ji's efforts, today India is a leading global player in IT and Communications.

Technology plays crucial role in society today. Use of IT has revolutionised the service delivery system. Technological advancement gives impetus to economic and social progress. Rajasthan Government has introduced IT-enabled automated services so that the common man could derive the benefits of various government schemes and programmes in a transparent manner.

We have created an environment filled with opportunities for startups and youth. We firmly believe that through technological advancements, we will grow together and be able to create a new Rajasthan as Digital Rajasthan.

सूची

नागरिक सेवाओं की उपलब्धता हेतु सार्वजनिक इंटरफेस .... 1 - 3
जन आधार योजना 1
जनसूचना पोर्टल 2
राजस्थान सम्पर्क 2
ई-मित्र 3
राजकिसान साथी 3

इंफ्रास्ट्रक्चर .... 4 - 6
स्टेट डाटा सेंटर 4
वीडियो वॉल (Video Wall) 4
राजनेट (RajNet) 4
राजस्वान (RajSWAN) 4
राज वी.सी. - ई-गवर्नेंस संचार का मूलभूत आधार 4
राज वाई-फाई (Raj WiFi) - राज्य के निवासियों के लिए देश की सबसे व्यापक राज वाई-फाई सुविधा 5
राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय 5
राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी 5
अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर 6
वन्यजीव निगरानी और अवैध शिकार विरोधी प्रणाली (WS&APS) 6

कॉमन प्लेटफार्म .... 7 - 11
राज ई-साईन 7
ई-संचार 3.0 7
राजस्थान सिंगल साईन-ऑन (RajSSO) 7
राज ई-वॉल्ट 8
राजपेमेंट प्लेटफॉर्म 8
राज उद्योगमित्र - MSME Act 2019 9
राजनिवेश 9
राजस्थान सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (SWCS) 9
ई-बाजार 9
ई-बिजनेस पोर्टल 10
जनकल्याण 10
राजधरा 10
3D सिटी 11
राज मेल (Raj Mail) 11
बिग डाटा और डाटा विश्लेषण 11

ऑफिस ऑटोमेशन 12
राजकाज -एकीकृत ई-ऑफिस 12
राज ई.आर.पी. (Raj ERP) 12

एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स .... 13 - 14
राजकैड (RajCAD) 13
आर.टी.आई. पोर्टल 2.0 (RTI Portal) 13
राजस्थान भर्ती पोर्टल (Rajasthan Recruitment Portal) .... 13 - 14

i-स्टार्ट .... 15 - 16
QRate 15
राजस्थान इन्क्यूबेशन सेंटर 15
चैलेंज फॉर चेंज 15
सरकारी खरीद 15
i-स्टार्ट स्कूल स्टार्टअप कार्यक्रम 16
i-स्टार्ट ग्रामीण स्टार्टअप कार्यक्रम 16

कोविड-19 महामारी के दौरान DoIT&C का योगदान 17

पुरस्कार .... 18 -19

संपर्क करें .... 20 -21

नागरिक सेवाओं की उपलब्धता हेतु सार्वजनिक इंटरफेस

जन आधार योजना

'एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान'।
जन आधार योजना अपने प्रसार एवं उपयोगिता के आधार पर देश की सबसे बडी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्लेटफॉर्म बन गयी है।

- योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित 114 लोक कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का 7.13 करोड लाभार्थियों तक सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है।
- जन आधार के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया गया है एवं अब तक 44,000 करोड रू. के नकद लाभ प्रदान किये गये हैं।
- अब तक की गणना के अनुसार 103 करोड डीबीटी लेनदेन संपन्न हो चुके हैं।
- लाभार्थियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता की सुरक्षा के लिहाज से लाभ हस्तांतरण से लेकर निकासी तक सभी लेनदेन के लिए पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस. अलर्ट की सुविधा प्रदान की गयी है।
- यह योजना लाभार्थी की बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चिता के आधार पर प्रदान की जाने वाली गैर-नकद लाभों के हस्तांतरण के लिए जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सब्सिडी के साथ मिलने वाले राशन (पी.डी.एस. के माध्यम से)आदि के लिए भी उपयोगी और प्रभावी माध्यम है।
- आमजन को सरलता से योजनाओ के लाभ देने के लिए भौतिक सत्यापन व दस्तावेज के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का कार्य जन आधार के माध्यम से प्रारम्भ कर दिया गया है।

जनसूचना पोर्टल

राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत द्वारा इस पोर्टल का शुभारंभ 13 सितम्बर, 2019 को किया था। यह पोर्टल राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही डिजिटल सूचनाओं पर आधारित है। पोर्टल का प्रारूप इन डिजिटल सूचनाओं की आमजन तक उपलब्धता एवं उपयोगिता के आधार पर बनाया गया है। जनसूचना पोर्टल द्वारा उपलब्ध डाटा को भौगोलिक आधार पर संधारित किया गया है ताकि किसी पंचायत / निगम वार्ड में रहने वाला सामान्य नागरिक भी अपने क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं एवं नागरिक संस्थाओं की जानकारी सुगमता से प्राप्त कर सके।

पोर्टल पर उपलब्ध योजना पात्रता मॉड्यूल (Scheme Eligibility Module) - राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए नागरिकों की पात्रता को दर्शाता है। जनआधार डेटाबेस का उपयोग करते हुए इस मॉड्यूल के माध्यम से 14,987 निवासियों की पात्रता को सत्यापित किया गया है।

पोर्टल पर उपलब्ध Penetration Module के माध्यम से विभागों के अधिकारियों को योजनाओं का वास्तविक आंकलन व मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

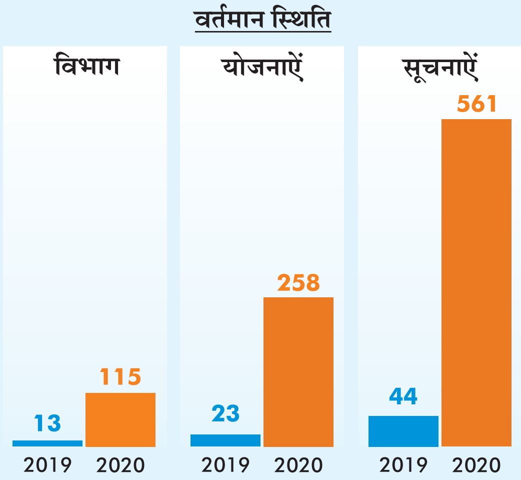

राजस्थान सम्पर्क

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल (CM Helpline - 181) - यह पोर्टल राज्य के नागरिकों एवं विभागीय उपयोगकर्ताओं को प्रभावी शिकायत निवारण हेतु एकीकृत मंच प्रदान करता है। राज्य के निवासी सभी सरकारी विभागों, संस्थाओं, एजेंसियों और राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित किसी भी शिकायत को विभिन्न माध्यमों जैसे - कॉल सेंटर (CM Helpline - 181), राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, मोबाईल एप्लीकेशन, ई-मेल, चैटबॉट, ई-मित्र कियोस्क तथा व्हाट्सएप के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं।

यह एक अत्याधुनिक 400 सीट क्षमता वाला नागरिक संपर्क केंद्र है, जिसके द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी और शिकायत निवारण की सुविधा हेतु विभिन्न सेवाऐं सूचना केंद्र के रूप में प्रदान की जाती हैं।

अब तक लगभग 87.69 लाख शिकायतें दर्ज की गयी हैं जिनमें से लगभग 83.39 लाख शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। (निपटारा प्रतिशत - 98.52)

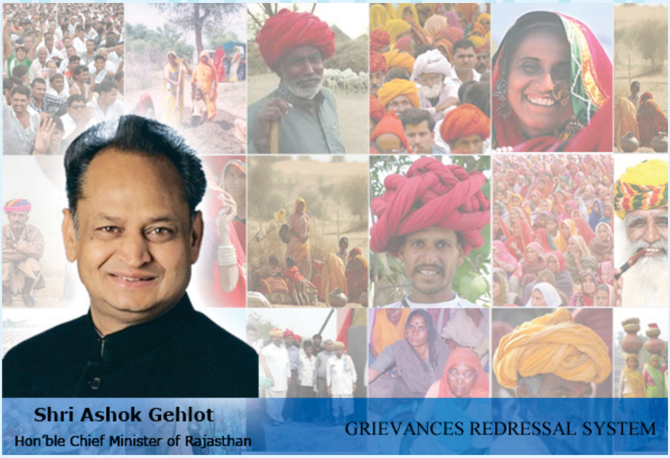

ई-मित्र

नागरिक सेवाओं की त्वरित और सुविधाजनक उपलब्धता हेतु प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी और निजी नागरिक-केंद्रित सेवाओं को आमजन के दरवाजे तक पारदर्शी एवं लागत प्रभावी ढंग से पहुंचाने हेतु ई-गवर्नेंस के तहत ई-मित्र मंच स्थापित किया है।

वर्तमान में राज्य के सभी 33 जिलों में 85,000 से अधिक ई-मित्र कियोस्कों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 500 से अधिक G2C और B2C सेवाऐं प्रदान की जा रही है। ई-मित्र नेटवर्क के माध्यम से प्रतिमाह लगभग 70-80 लाख से अधिक लेनदेन सम्पन्न किये जाते हैं।

राजस्थान ई-मित्र परियोजना के विस्तार स्वरूप ई-मित्र प्लस मशीनों की स्थापना कर रहा है। इस परियोजना के तहत राज्य में 14891 ई-मित्र प्लस मशीनें स्थापित की गई हैं, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर 9891 मशीनें और शहरी क्षेत्रों में 5000 मशीनें स्थापित की गई हैं। इन मशीनों के माध्यम से 70 से अधिक सेवाऐं जैसे - बिलों का भुगतान, विभिन्न रिचार्ज आदि की उपलब्धता प्रदान की जा रही हैं।

राजकिसान साथी

राजकिसान साथी पोर्टल राज्य के कृषकों एवं कृषि आधारित/संबंधित वाणिज्यिक संस्थानों को ऑनलाईन G2C, G2B एवं G2G सेवाऐं प्रदान करने हेतु एक डिजिटल मंच है।अब तक 2.8 लाख से अधिक किसान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभान्वित हो चुके हैं।

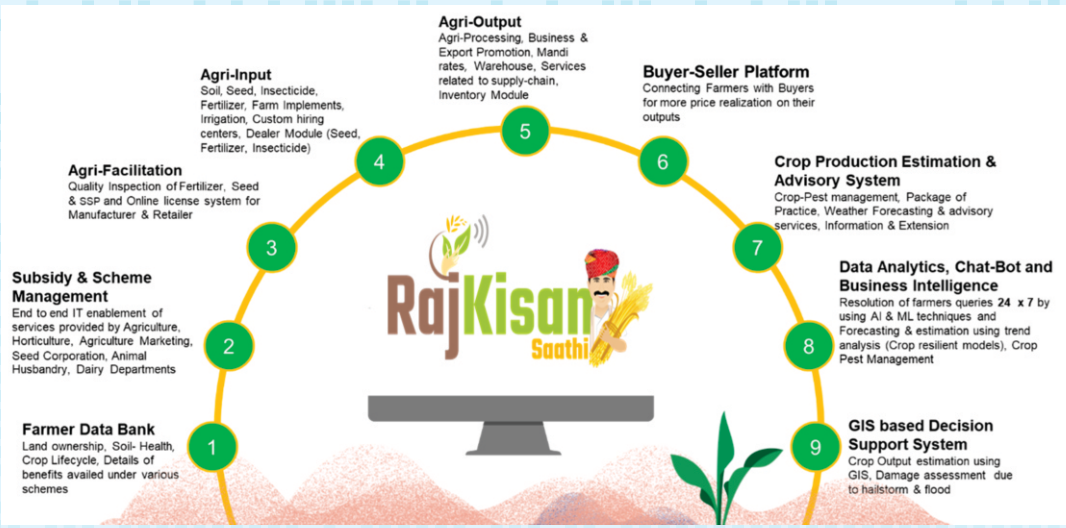

इंफ्रास्ट्रक्चर

स्टेट डाटा सेंटर

राज्य सरकार ने जयपुर में 600 रैक के साथ अत्याधुनिक, टियर-4 डाटा सेंटर शुरू किया है। अब, राज्य सरकार अन्य राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के विभागों/पीएसयू/एजेंसीयों/ संगठनों/स्टार्टअप्स और निजी क्षेत्र के संस्थानों को लागत के आधार पर निम्नलिखित स्टेट डाटा सेंटर सेवाऐं प्रदान कर रही है :

1. फुल रैक/हॉफ रैक स्पेस
2. अवसंरचना एक सेवा के रूप में (IaaS)
3. बैकअप सेवाऐं
4. वी.पी.एन. सेवाऐं
5. प्रबंधित सेवाऐं

वीडियो वॉल (Video Wall)

सरकार में जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावशीलता में गुणवत्ता लाने के साथ ही विभिन्न G2G, G2B, और G2E सेवाओं की जानकारी आमजन तक वितरित करने के लिए वीडियो वॉल परियोजना शुरू की गयी है।

इस परियोजना के अंतर्गत सरकार ने सभी 33 जिला मुख्यालयों और 295 ब्लॉक मुख्यालयों के प्रमुख स्थानों पर एल.ई.डी. वीडियो वॉल स्थापित की है।

राजनेट (RajNet)

प्रदेश में ई-गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक 18,500 आई.पी. फोन लगाये जा चुके हैं।

मैसर्स बी.बी.एन.एल. द्वारा भारतनेट परियोजना के तहत 8505 ग्राम पंचायतों के लिए राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर उच्च-गति बैंडविड्थ उपलब्ध करवायी जा चुकी है।

राजनेट परियोजना के अंतर्गत 800 से अधिक सरकारी ईमारतों/कार्यालयों में उच्च बैंडविड्थ और थ्रुपुट की सुविधा उपलब्ध करवायी जा चुकी है।

राजस्वान (RajSWAN)

राजस्वान परियोजना के अंतर्गत 4800 से अधिक सरकारी ईमारतों, जिनमें 5200 से अधिक कार्यलय शामिल हैं, के लिए Captive Optical Fiber Cable, Point to Point (P2P) और MPLS (Multi-Protocol Label Switching) के माध्यम से उच्च बैंडविड्थ एवं थ्रुपुट कनेक्टिविटी क्षमता का विकास किया गया है।

राज वी.सी. (Raj V.C.) - ई-गवर्नेंस संचार का मूलभूत आधार

राज्य ने विभिन्न सरकारी विभागों में 570 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टूडियो रूम स्थापित किए हैं। जिनके माध्यम से राज्य में सालाना 5000 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित किये जा रहे हैं।

राज्य ने एक सॉफ्टवेयर आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी खरीदी है। यह सेटअप राज्य के निवासियों को जोडने के लिए स्थापित किया गया है। इस मंच का उपयोग करते हुए राज्य भर में 1500 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित किये जा रहे हैं।

CM Helpline – 181 सहित सचिवालय, सभी सरकारी विभागों, कलेक्ट्रेट और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों के बीच सीधे संवाद हेतु अब तक 18000 से अधिक आई.पी. टेलीफोन स्थापित किए गए हैं।

राज वाई-फाई (Raj WiFi) - राज्य के निवासियों के लिए देश की सबसे व्यापक वाई-फाई सुविधा

इस परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार सभी 9000 ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में निवासियों के लिए मुफ्त WiFi की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और नगरपालिका वार्ड आदि शामिल हैं।

इस सुविधा के माध्यम से राज्य के आमजन तक सहायक सामग्री, सूचनाओं और अनगिनत सरकारी और निजी सेवा वितरण ऐप्स और वेबसाइटों की उपलब्धता एवं उपयोगिता को बढाया गया है।

वन्यजीव निगरानी और अवैध शिकार विरोधी प्रणाली (WS&APS)

यह प्लेटफॉर्म रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जवाईभाग लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व और झालाना नेचर पार्क आदि जंगल के संरिक्षत क्षेत्रों के लिए हाईब्रिड मॉडल पर आधारित हाई एंड थर्मल/ऑप्टिकल कैमरे, पॉईंट-टू-पॉईंट वॉयरलैस नेटवर्क और संचार उपकरण, सौर उर्जा प्रणाली और ड्रोन आदि से लैस एक एकीकृत निगरानी तंत्र प्रदान करता है।

निगरानी तंत्र से प्राप्त आंकडे :-

सूचना का प्रकार	संख्या
अलर्ट/अलार्म	93 लाख बार से ज्यादा
दर्ज घटनाऐं	9567

राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय

400 करोड़ रू. के बजट प्रावधान के अंतर्गत जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। इस संस्थान की स्थापना को विशिष्ट एवं क्षेत्र केंद्रित लक्ष्यों की प्राप्ति की परिकल्पना को आधार बनाकर किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) डोमेन में मानव संसाधन आवश्यकता में अपेक्षित एवं उल्लेखित वृद्धि को पूर्ण किया जायेगा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रौद्योगिकियों जैसे वेल्थटेक, ब्रोकिंग, SaaS, इन्शोरटेक, वैकल्पिक उधार, भुगतान इत्यादि का उपयोग एवं अभिवृद्धि की जायेगी।

राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी

200 करोड़ रू. के बजट प्रावधान के साथ राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना सूचना केंद्र, जयपुर में की जायेगी। यह केंद्र इंजीनियरिंग स्नातकों, प्रबंधन स्नातकों, अन्य स्नातकों और यहां तक कि स्नातक से नीचे स्तर के छात्रों के लिए भी एक विद्यालय की भांति कार्य करेगा। इस केंद्र के माध्यम से विभिन्न प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा उभरती हुयी प्रौद्योगिकियों जैसे Artificial Intelligenge, Machine Learning, Robotics, Augmented Reality, Virtual Reality, Big Data Analytics एवं Quantum Computing आदि हेतु सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को संचालित किया जा सकेगा।

अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर

राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों सहित सभी 33 जिलों में जी.पी.एस. और सी.सी.टी.वी. आधारित एकीकृत सुरक्षा समाधान के लिए कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटक सम्मिलित हैं –

- वीडियो निगरानी प्रणाली।
- डायल 100 नियंत्रण प्रणाली।
- फोरेंसिक अनुसंधान प्रणाली।
- ITMS (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम)
- वाहन ट्रैकिंग प्रणाली।
- भौगोलिक सूचना प्रणाली।

परियोजनान्तर्गत प्रगति निम्न प्रकार है:-

विषय	विवरण
कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर की स्थापना	सभी 7 संभागों और 26 जिला मुख्यालयों पर स्थापना एवं सुचारू रूप से संचालन
वीडियो निगरानी तंत्र	6588 कैमरे लाइव तथा 772 ऑफ लाईन कैमरों के द्वारा सतत निगरानी
डायल 100 नियंत्रण तंत्र	सभी 33 जिलों मे कार्यरत

कॉमन प्लेटफार्म

राज ई-साईन

राज ई-साइन एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है, जो सभी आधार (यू आई डी) धारकों को बिना भौतिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन प्राप्त किए, किसी दस्तावेज़ पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करती है। यह आधार की eKYC सेवा का उपयोग करके हस्ताक्षरकर्ता की पहचान को प्रमाणित करने के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर आसान, कुशल और सुरक्षित हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करती है।

राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी, आई.टी. अधिनियम 2000 की धारा 24 के अनुसार डिजिटल प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रमाणन प्राधिकरण (CA) के रूप में कार्यरत है।

ई-संचार 3.0

यह सरकार द्वारा संचालित विभिन्न ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों हेतु कई संचार चैनलों और नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए एक केंद्रीकृत संचार माध्यम है। यह पुश एस.एम.एस., पुल एस.एम.एस., आउटबाउंड वॉयस कॉल, आउटबाउंड आई.वी.आर.एस. के लिए API interface प्रदान करता है।

इस माध्यम ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लडाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी सहायता से महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले एडवाईजरी संदेश नागरिकों/कोरोना वॉरियर्स/सरकारी कर्मचारियों को प्रेषित किये गये साथ ही प्रवासियों की सूचना/नियमों/पोलिसी/महामारी के संबंध में नवीनतम सूचनाओं हेतु आई.वी.आर.एस. आधारित सर्वेक्षण और स्वचालित कॉल्स किये गये।

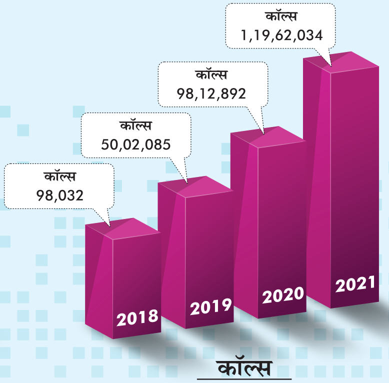

राजस्थान सिंगल साईन-ऑन (RajSSO)

RajSSO द्वारा एक ही URL– https://sso.rajasthan.gov.in और एक डिजिटल पहचान के माध्यम से राज्य सरकार के सभी अनुप्रयोगों और प्रणालियों के लिए केंद्रीकृत पहुंच प्रदान की जाती है। सभी पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य मूल्य-वर्धित सेवाएं हैं -

- राजमेल, एक निःशुल्क सरकारी ई-मेल एकाउंट बनाने के लिए
- दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए ई-साइन सुविधा
- ई-वॉल्ट (डिजिटल लॉकर) सुविधा

RajSSO के माध्यम से अभी तक 242 G2G एप्लीकेशन को 9 लाख से अधिक राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। साथ ही 161 G2C/G2B/G2E एप्लीकेशनों को वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/उद्योग/बैंक (राज्य में सभी बैंक/शाखाऐं)/ ई-मित्र/सी.एस.सी. कियोस्क/निवासी (स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) सहित 2.29 करोड़ संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

राज ई-वॉल्ट

राज ई-वॉल्ट
Raj eVault

राज्य सरकार द्वारा डिजिटलीकरण को बढावा देने के लिए राज ई-वॉल्ट परियोजना की शुरूआत की गयी है। यह नागरिकों के लिए डिजिटल सामग्री (दस्तावेज/लाइसेंस/ ECM फाइलें) को सुरक्षित रखने के लिए एक डिजिटल सामग्री भंडार के रूप में कार्य करता है। विभिन्न विभागों, लिगेसी सिस्टम्स और थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन्स के साथ एकीकरण के माध्यम से यह नागरिकों तक इस डिजिटल सामग्री की एकीकृत और सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है।

राज ई-वॉल्ट के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाऐं निम्नानुसार हैं -

दस्तावेज/प्रमाणपत्र नागरिकों को राज ई-वॉल्ट के लिए विकसित ऑनलाईन एप्लीकेशन https://evault.rajasthan.gov.in/rajevault/# के माध्यम से उपलब्ध हैं।

वर्तमान में यह राजस्थान के 21 विभागों को विभागीय दस्तावेज/फाइलें और नागरिकों को जारी किए गए प्रमाण पत्र/लाइसेंस आदि के रखरखाव और भंडारण की सेवाऐं प्रदान कर रहा है।

राजपेमेंट प्लेटफॉर्म

₹PP

राज्य के ई-गवर्नेंस वीजन की अनुपालना की दिशा में एक कदम आगे बढाते हुए सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों की सभी भुगतान और संवितरण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजपेमेंट प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है।

RPP को लाइव करने के साथ ही इसके माध्यम से 55 से अधिक विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों को भुगतान संग्रह और संवितरण की सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्लेटफॉर्म से संबंधित आंकडे

	धनराशि	
संग्रह	4.25 Crore +	Rs. 19000 + Crore
अदायगी	1.50 Crore +	Rs. 37000 Crore

राज उद्योगमित्र – MSME Act 2019

राज उद्योगमित्र (https://rajudhyogmitra.rajasthan.gov.in) का शुभारंभ 12 जून, 2019 को किया गया था। इस प्लेटफॉर्म का विकास MSMEs को राज्य कानूनों के तहत छूट की मंजूरी के साथ प्रावधान कर MSMEs के संवर्धन हेतु उद्योग विभाग एवं ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमेंट प्रोमोशन (BIP) के लिए किया गया था। यह प्रावधान तीन वर्ष की समयावधि के लिए किये गये हैं। यह आवेदनकर्ता को वास्तविक समय में 'Declaration of Intent' के आधार पर बिना किसी मैनुअल उपयोगकर्ता हस्तक्षेप के 'Acknowledgement Letter' (पावती पत्र) प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

राजनिवेश

RAJ NIVESH
Your One-Stop-Shop for Investments
Government of Rajasthan

राजनिवेश (https://rajnivesh.rajasthan.gov.in) का शुभारंभ 16 दिसंबर, 2020 को किया गया था। इस प्लेटफॉर्म को महत्वपूर्ण निवेश प्रस्तावों (10 करोड़ रू. से अधिक) को सुविधाजनक बनाये जाने के साथ ही अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाये जाने के लिए उद्योग विभाग एवं ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमेंट प्रोमोशन (BIP) के लिए विकसित किया गया है।

यह प्लेटफॉर्म प्रस्तावित निवेशकों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए ऑनलाइन (पेपरलैस) प्रश्न समाधान/आवेदन जमा करने/ई-भुगतान/ऑनलाइन आवेदन निपटान और संबंधित विभागों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अनुमोदन/मंजूरी/एनओसी/लाईसेंस आदि जारी करने के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है।

राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से 15 विभागों की 134 सेवाऐं प्रदान की जा रही हैं।

राजस्थान सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (SWCS)

SWCS – https://swcs.rajasthan.gov.in प्रस्तावित निवेशकों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (10 करोड़ रू. तक) के प्रश्न समाधान / ऑनलाईन आवेदन - पेपरलैस / ई-भुगतान / संबंधित विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन निपटान आदि के लिए संपर्क हेतु एकल बिंदु की तरह कार्य करता है। साथ ही इसके माध्यम से संबंधित विभाग द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अनुमोदन / मंजूरी / एन.ओ.सी. / लाइसेंस आदि जारी करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

यह एकल केंद्र के रूप में 16 विभागों की विभिन्न प्रकार की 135 सेवाऐं प्रदान करता है। अब तक 2,21,818 अनुमोदन/मंजूरी/एन.ओ.सी. /लाईसेंस आदि इसके माध्यम से जारी किये जा चुके हैं।

ई-बाजार

e-Bazaar™
Rajasthan Online Store

ई-बाजार एक वेब आधारित बिक्री और सूची प्रबंधन प्रणाली है जो सामाजिक-आर्थिक विकास और राज्य के हस्तशिल्प/उद्योगों को बढावा देने के लिए एकीकृत समाधान पैकेज के साथ उत्पादों के विपणन और बिक्री के लिए कारीगर/बुनकर/स्वयं सहायता समूहों/राज्य के सरकारी संगठनों और स्टार्टअप्स का समर्थन करती है। ई-बाजार प्लेटफॉर्म पर अभी तक 650 से अधिक उत्पादों को सूचीबद्ध किया जा चुका है, साथ ही 65000 से अधिक ऑर्डर संसाधित (Process) किये जा चुके हैं।

ई-बिजनेस पोर्टल

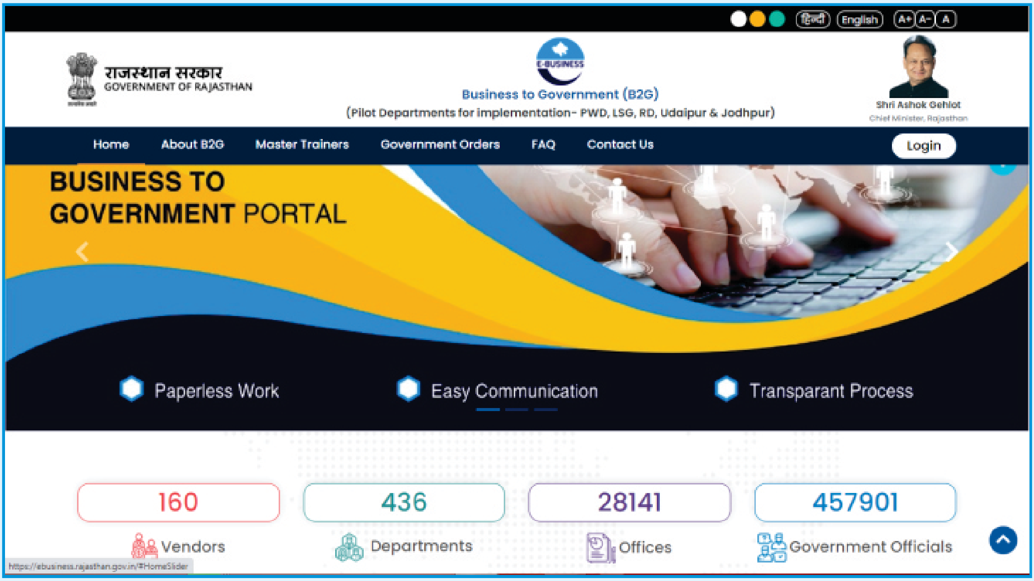

ई-बिजनेस पोर्टल सरकारी विभागों और व्यावसायिक संस्थाओं के बीच आसानी से व्यापार करने और निर्बाध संचार को बढावा देने के लिए एक केंद्रीकृत वर्कफ्लो-आधारित एप्लीकेशन के रूप में कार्य करता है।

जनकल्याण

जन कल्याण (पब्लिक वेलफेयर पोर्टल)

जनकल्याण पोर्टल https://www.Jankalyan.rajasthan.gov.in सभी सरकारी विभागों/पी.एस.यू./संगठनों/बोर्डों की महत्वपूर्ण जानकारी जैसे सरकारी आदेश, परिपत्र, अधिसूचनाऐं, नीति-दिशानिर्देश, सरकारी वेबसाइटों के लिंक और मोबाईल एप्लीकेशन तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए लोक कल्याणकारी पोर्टल है।

राजधरा

rajdharaa

राजधरा राज्य की भौगोलिक संपत्ति का स्वदेशी जी.आई.एस. आधारित डेटाबेस है। यह राज्य की प्रशासनिक और राजस्व सीमाओं, जल निकायों, परिवहन नेटवर्क आदि का हाई-रिजॉल्यूशन आधारित इमेजरी का आधार मानचित्र है।

- जी.आई.एस. आधारित मोबाईल ऐप 'RajCovidInfo', वेब एप्लीकेशन 'Covid-19 GIS' और 'CQAS' ने राज्य में कोविड-19 महामारी की ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, कंटेनमेंट और रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- 'राजस्थान पर्यटन आधिकारिक ऐप' (Rajasthan Tourism Official App) नागरिकों और पर्यटकों को दिशा, सूचना और रूचि के अनुरूप स्थानों/पर्यटन स्थलों के चयन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।
- औद्योगिक लैंडबैंक राज्य के निवेशकों के लिए बनाया गया है।
- विभिन्न विभागों और योजनाओं के लिए जी.आई.एस.-आधारित वेब और मोबाईल इंटरफेस विकसित किये गये हैं, जिसके माध्यम से परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, फील्ड स्तर के अधिकारियों तक सेवा वितरण का निरीक्षण, स्थानिक और गैर-स्थानिक डाटा का संग्रह और प्रसार, एवं अंतर-क्षेत्रीय योजनाओं का भू-स्थानिक विश्लेषण किया जा सकता है।
- लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे सिविल कार्यों की प्रभावी योजना निर्माण और निगरानी के लिए जी.आई.एस. आधारित कार्यप्रवाह प्रबंधन प्रणाली लागू की गयी है।

3D सिटी

जयपुर 3D सिटी सॉल्यूशन एक 3D भू-स्थानिक स्वरूप में जयपुर शहर का समृद्ध 3D प्रस्तुतीकरण है, जिसमें बडे पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन योजना, टाउन प्लानिंग, मॉडलिंग और प्रभावी आकलन को समग्र रूप से बनाने, चित्रण करने, अनुकरण करने, योजना निर्माण और उनके निष्पादन की क्षमता विकसित करता है।

राज मेल (Raj Mail)

डिजिटल इंडिया मिशन के तहत राजस्थान पूरे देश में बढत के तौर पर भाषा विभाजन को दूर करने के लिए भाषायी ई-मेल सेवाओं की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन गया है।जिसके माध्यम से राज्य के निवासियों के लिए @rajasthan.in डोमेन पर मुफ्त ई-मेल खाते के साथ ही @राजस्थान.भारत डोमेन पर हिंदी में ई-मेल पता बनाने की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।

राज मेल के माध्यम से 50 लाख ई-मेल खाते अभी तक बनाए जा चुके हैं, जिससे यह देश में सबसे व्यापक ई-मेल परियोजनाओं में से एक बन गयी है।

बिग डाटा और डाटा विश्लेषण

राज्य ने नागरिक सेवाओं के वितरण में सुधार करने के उद्देश्य से सभी विभागों के लिए डाटा को अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए एक सामान्य डाटा और विश्लेषण मंच बनाया है।

ऑफिस ऑटोमोशन

राजकाज –एकीकृत ई–ऑफिस

एकीकृत कार्यालय स्वचालन एप्लीकेशन 'राज–काज' को राज्य भर में लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अंत:–सरकारी और अंतर–सरकारी लेनदेन में अतिरिक्त दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता लाना है। राजकाज परियोजनान्तर्गत मुख्य मॉड्यूल्स अवकाश, अचल सम्पत्ति विवरण, वार्षिक कार्य मूल्यांकन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, फाईल ट्रेकिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम, डाक, एम्प्लोय इन्फोर्मेशन सिस्टम, राजकीय आवास आवंटन, स्टोर मैनेजमेन्ट इत्यादि लागू किये जा रहे है।

राजकाज परियोजना से संबंधित आंकडे

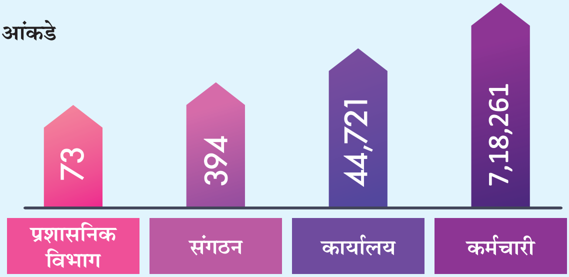

राज ई.आर.पी. (Raj ERP)

- Raj ERP राजस्थान सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यान्वयन के लिए एक मानक ERP Suite है। यह राजस्थान सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को परिचालन उत्पादकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं की प्रक्रिया स्वचालन क्षमता प्रदान करता है।
- यह राज–पैमेंट, एस.आई.पी.एफ., जी.पी.एफ. जमाओं के लिए ई–ग्रास और आर.जी.एच.एस. पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान PSU's के कर्मचारियों को मान्यता प्रदान करने के लिए एकीकृत किया गया है।
- वर्तमान में यह RSMML, JMRC, AU-K, RISL और 5 डिस्कॉम - JVVNL, AVVNL, JDVVNL, RVPNL, RVUNL में लागू किया जा चुका है।

एप्लीकेशन एण्ड सॉफ्टवेयर्स

राजकैड (RajCAD)

परियोजनाओं के विकास, रखरखाव और निरंतरता को बनाये रखने के लिए विभाग ने in-house सरकारी संसाधनों की क्षमता का बेहतर उपयोग 'एप्लीकेशन डवलपमेंट सेंटर (RajCAD), जयपुर' की स्थापना के माध्यम से किया है।
RajCAD के अंतर्गत निम्नलिखित डोमेन में विशेषज्ञता हासिल की जा रही है –

- बी.आई. और डाटा एनालिटिक्स (Tableau, SAS, Power BI)
- वैब एप्लीकेशन डवलपमेंट (Dot Net, PHP, JAVA)
- बिजनेस एनालाइसिस
- नेटवर्किंग और संचार
- मोबाईल एप्लीकेशन डवलपमेंट
- जी.आई.एस. और रिमोट सेंसिंग
- उभरती प्रौद्योगिकियां –AI, IOT, Cloud Computing, Blockchain (अगले चरण में)
- एप्लीकेशन टेस्टिंग और सुरक्षा ऑडिट, आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा (Data, Firewall, Antivirus etc.)

आर.टी.आई. पोर्टल 2.0 (RTI Portal)

सूचना का अधिकार
Right to Information
Government of Rajasthan

यह पोर्टल राजस्थान सरकार के सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों/सरकारी कार्यालयों/संगठनों के संबंध में आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अनिवार्य सभी सूचनाओं और सेवाओं तक एकल बिंदु उपलब्धता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

- आर.टी.आई. 2.0 को विकसित, परिनियोजित और लाईव किया जा चुका है।
- ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदनों और अपीलों को दर्ज करने और संसाधित करने में उपयोगकर्ताओं की मदद करने के लिए एक हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है।
- पोर्टल पर पंजीकृत सभी विभागों के लिए आर.टी.आई. पोर्टल के संबंध में ऑनलाईन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। यह प्रशिक्षण एक नियमित प्रक्रिया है।
- 275 विभागों और 58,200 सरकारी अधिकारियों को इस पोर्टल पर सहायक जन-सूचना अधिकारी (ASPIO), जन-सूचना अधिकारी (PIO) और प्रथम अपील अधिकारी (FAO) के रूप में पंजीकृत किया गया है।
- ई-साइन, वॉयस-टू-डिक्टेशन, स्वचालित अलर्ट (मेल और एस.एम.एस. के माध्यम से), विस्तृत डेशबोर्ड, आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आंतरिक अनुभागों में आवेदन हस्तांतरण जैसी सुविधाऐं शामिल की गयी हैं।

राजस्थान भर्ती पोर्टल (Rajasthan Recruitment Portal)

सत्यमेव जयते
Rajasthan Recruitment Portal

राजस्थान भर्ती पोर्टल राज्य सरकार के विभागों द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन और परीक्षाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान प्लेटफॉर्म है। यह एप्लीकेशन पोर्टल सभी उम्मीदवारों को राज्य भर में अपने घरों से अथवा ई-मित्र (सभी सरकारी सेवाओं के लिए सिंगल विंडो एक्सेस) के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए आवेदन की सुविधा प्रदान करता है।

लाभ

नागरिक :

- सभी भर्ती, आवेदन और सूचना के लिए सिंगल स्टॉप समाधान
- नई भर्तियों के लिए जारी की जाने वाली अधिसूचनाऐं
- विभिन्न रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
- ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा
- आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, और परिणाम प्रिंट की सुविधा
- एस.एम.एस. और ई-मेल के माध्यम से अपडेट प्राप्त करने की सुविधा
- ऑनलाइन प्रश्न और परिणाम आपत्तियां
- पूरा आवेदन इतिहास विवरण सुरक्षित लॉगिन सुविधा
- प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अनुकूलित डैशबोर्ड
- ई-मित्र के माध्यम से भी उपलब्धता

सरकारी विभाग/बोर्ड/आयोग :

- लाइव होने के समय में सुधार (समय में कमी)
- अतिरेक/अनावश्यक डाटा को हटाना
- ऑनलाइन आवेदन रसीद, आवेदन संपादन, ऑनलाइन आपत्ति
- रोल नंबर जनरेशन, परीक्षा केंद्र आवंटन, परिणाम अपलोड की सुविधा
- सारगर्भित रिपोर्ट्स
- कुशल और तेज प्रणाली
- एक ही पद के लिए एक उम्मीद्वार द्वारा एक से अधिक आवेदनों को निरस्त करना
- शुल्क संग्रह और समाधान में आसानी

पोर्टल से संबंधित आंकडे –

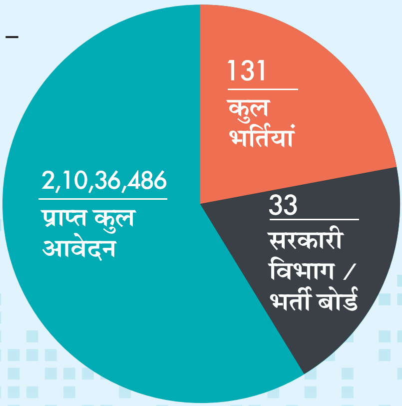

i - स्टार्ट

i-स्टार्ट राजस्थान, राज्य सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य नवाचारों को बढावा देना, रोजगार सृजित करना और निवेश की सुविधा प्रदान करना है। i-स्टार्ट राजस्थान कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां निम्नानुसा हैं –

- यह कार्यक्रम स्टार्टअप्स, इन्क्यूबेटरों और VCs के लिए व्यवसाय करने और राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त सभी लाभों और प्रस्तावों का आकलन करने के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है।
- यह स्टार्टअप्स को प्रासंगिक हितधारकों जैसे – सलाहकार, निवेशक, एक्सीलरेटर और इनक्युबेटर्स के साथ जुडने में सहायता प्रदान करता है।

Q रेट (Q rate)

Qrate राज्य स्टार्टअप्स के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है, जो स्टार्टअप्स को उनकी सफलता की संभावना बढाने और धन प्राप्त करने में मदद करने के लिए 3 प्रमुख घटकों (स्टार्टअप स्कोरकार्ड, कौशल निर्माण और स्टार्टअप हेतु धन उगाहने में सहायता) का संयोजन है।

राजस्थान इन्क्यूबेशन सेंटर

इन्क्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप समूहों को स्थान और संसाधनों (हाई-स्पीड इंटरनेट, डाटा सेंटर, फर्नीचर, वर्क स्टेशन, विश्राम क्षेत्र) की सुविधा प्रदान करता है, ताकि उन्हें अपने व्यवसाय को विस्तृत क्षेत्र में विस्तार करने से पूर्व सुदृढता प्रदान की जा सके। राजस्थान सरकार सभी संभाग मुख्यालयों पर इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने जा रही है।

टेक्नो-हब देश का सबसे बडा स्टार्टअप हब है, जिसमें 700 से अधिक स्टार्टअप्स के बैठने की जगह और 1,50,000 वर्गफुट का इन्क्यूबेशन स्पेस है। यहां विश्व स्तरीय सुविधाऐं जैसे – वातानुकूलित फ्री वर्क स्पेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मेंटरशिप, मार्केट कनेक्ट, वी.सी. और इन्वेस्टर कनेक्ट साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/विशेषज्ञों का मार्गदर्शन शामिल हैं।

चैलेंज फॉर चेंज

चैलेंज फॉर चेंज कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा युवाओं, कामकाजी पेशेवरों, उद्यमियों को अपने स्वयं के नवीन विचारों के साथ आगे आने के लिए या सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना में परिवर्तन लाने के लिए आमंत्रित करने की एक पहल है।

राजस्थान सरकार ने अब राज्य में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स और वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्यमों को प्रोत्साहित करने और आगे बढाने के लिए **'राजीव @75'** के तहत राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड्स के शुभारंभ के साथ ही राज्य के इनोवेटर्स के साथ अपनी प्रतिबद्धता का विस्तार किया है।

पुरस्कार उन स्टार्टअप्स/उद्यमियों/एम.एस.एम.ई. को दिये जायेंगे जो i-स्टार्ट राजस्थान कार्यक्रम के चैलेंज फॉर चेंज प्लेटफॉर्म के तहत शुरू की गई भव्य चुनौतियों में भाग लेंगे। इन चुनौतियों के तहत शीर्ष विजेता को 2 करोड़ रूपये, उपविजेता को 1 करोड़ रूपये और अन्य तीन विजेताओं को 50 लाख रूपये दिए जाऐंगे।

सरकारी खरीद

राज्य में उद्यमिता विकास में तेजी लाने और पंजीकृत स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के विभाग चयनित कार्यों के लिए बिना टेंडर प्रक्रिया के 15 लाख तक के कार्य आदेश जारी कर सकेंगे।

i-स्टार्ट स्कूल स्टार्टअप कार्यक्रम

स्कूली छात्रों में उद्यमशीलता की मानसिकता को आत्मसात करवाने के लिए i-स्टार्ट के विस्तार स्वरूप स्कूल स्टार्टअप पहल को शामिल किया जा रहा है। राज्य इस कार्यक्रम के माध्यम से 9 शैक्षणिक क्षेत्रों में इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना और संचालन की परिकल्पना करता है। टेक्नो-हब, जयपुर की देखरेख में Hub & Spoke मॉडल पर आधारित 8 इन्क्यूबेशन केंद्र विद्यालयों के कक्षा 8वीं से 12 वीं तक के छात्रों को सलाह देंगे और मेंटर शिक्षकों को उद्यमिता और नवाचारों के पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

i-स्टार्ट ग्रामीण स्टार्टअप कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर उभरती उद्यमशीलता प्रतिभा को आकर्षित, समृद्ध और विकसित करना है। साथ ही ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान एवं उद्यम निर्माण में युवाओं और महिलाओं को बढावा देकर उनके संतुलित और समावेशी विकास के लिए उद्यमिता शिक्षा, हैंडहोल्डिंग और मेंटरशिप और वित्तीय सहायता के साथ आवश्यक सुविधाऐं प्रदान करना है। ग्रामीण स्टार्टअप कार्यक्रम के संभावित लाभार्थी महिला स्वयं सहायता समूह, निर्माता कंपनियां, सहकारी समितियां, ग्रामीण इनोवेटर्स/व्यक्ति, स्टार्टअप्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाऐं दे रहे हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान DoIT&C का योगदान

राजस्थान ने कोविड-19 महामारी के दौरान इसका सामना दृढ़ता और सकारात्मकता के साथ किया है। इस लडाई में राजस्थान सरकार को सुदृढता प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं -

1. विभिन्न गतिविधियों जैसे - कंटेनमेंट क्षेत्र, जिला और ब्लॉक स्तर, सीमा चौकियां, आदि से संबंधित सूचनाओं के आवागमन हेतु एक राज्य स्तरीय कोविड-19 वॉर रूम और राज्य के सभी 33 जिलों में जिला स्तरीय कोविड-19 वॉर रूम की स्थापना की।
2. 'आई.टी. वॉर रूम', सभी प्रमाणित सूचनाओं के लिए एक सूचना केंद्र के रूप में सूचना प्रवाह का केंद्र बिंदु बन गया था। जिसके माध्यम से24X7 सभी सरकारी सूचनाओं की विश्वसनीयता और प्रमाणिकता को बनाए रखा गया।
3. आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे - राजनेट, राजस्वान, ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के सरकारी कार्यालयों में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली ने कोविड-19 के खिलाफ कार्यवाही और आम आदमी को प्रदान की जाने वाली राहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4. ई-मित्र कियोस्क (राज्य के परिदृश्य में 80,000 से अधिक कियोस्क) के डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी नेटवर्क ने प्रभावी ढंग से राहत प्रदान की।
5. कोविड-19 के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने और इसके खिलाफ लडाई को और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग के लगभग 3000 अधिकारियों/ कर्मचारियों (सिस्टम एनालिस्ट, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर्स और सूचना सहायकों) ने अपनी सेवाऐं प्रदान की।
6. राजस्थान संपर्क (181 CM Helpline) ने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन परिदृश्य से संबंधित विभिन्न स्तरों पर संकट में नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए अंतिम पडाव शिकायत पोर्टल के रूप में कार्य किया। 50 से अधिक कर्मचारियों के साथ संचालित इस हेल्पलाइन केंद्र ने 24X7 नागरिकों की कॉल/शिकायतों/मांगों का समाधान किया।
7. COVID-19 STATISTICS एप्लीकेशन को कोविड-19 से संबंधित विभिन्न आंकडों जैसे - फंड आवंटन और व्यय, विभिन्न दवाऐं, ई-औषधि, ई-उपकरण, ऑक्सीजन की उपलब्धता, बिस्तरों की उपलब्धता (सामान्य, वेंटीलेटर के साथ आई.सी.यू. बेड और वेंटीलेटर के बिना आई.सी.यू. बेड) आदि से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करवाये जाने के लिए विकसित किया गया था। इसे covidinfo.rajasthan.gov.in पर भी सार्वजनिक किया गया है।

पुरस्कार और मान्यताएं

23rd National Conference on e-Governance
Second Day - Session 4 on 8th February, 2020
Webcast By: National Informatics Centre

Raj Masters – Centralized Master Data Hub:
Digital Transformation Award, 2019

Document Verification & Authentication Engine
Award for Excellence-IMC
Digital Technology Awards 2019

पुरस्कार

Disaster Management Information System
Award for Excellence-IMC
Digital Technology Awards 2019

e-Sign CA (Certifying Authority)
Digital Transformation Award 2019

BSDC Complex, Econaur Sustainability
Awards 2021

संपर्क करें

Public Interface for Service Delivery

Project	OIC Name and Designation	Mobile No.	E-mail
1.1 Jan Aadhaar Yojana	Sh. Mukesh Sharma, ACP(DD)	9414995870	mukeshks.doit@rajasthan.gov.in
1.2 Jansoochna Portal	Sh. Sudarshan Singh Deora, ACP(DD)	9950733119	sudarshansd.doit@rajasthan.gov.in
1.3 Rajasthan Sampark	Sh. G. K. Sharma, GM(T)	7737752957	gksharma@rajasthan.gov.in
1.4 E-Mitra	Sh. R K Sharma, AD	9413387309	rksharma@rajasthan.gov.in
1.5 Rajkisan Saathi	Ms. Monika Chaudhary, ACP(DD)	9784296702	monikac.doit@rajasthan.gov.in

Infrastructure

Project	OIC Name and Designation	Mobile No.	E-mail
2.1 State Data Centre	Sh. Ashutosh M. Deshpande, TD	9413387308	amdeshpande@rajasthan.gov.in
2.2 Video Wall	Sh. Ved Prakash Yadav, SA(JD)	9413387317	vp-yadav@rajasthan.gov.in
2.3 RajNet	Sh. Ashish Kumar Gupta, ACP(DD)	9413611116	ashishkg.doit@rajasthan.gov.in
2.4 RajSWAN	Sh. Satish Samariya, ACP(DD)	9950822607	ssamariya.doit@rajasthan.gov.in
2.5 RajVC - Communication backbone of e-Governance	Sh. Ramesh Dewanda, SEMT-SPO	9680702000	N.A.
2.6 RajWiFi - India's most extensive state WiFi facility for residents	Sh. Ashish Kumar Gupta, ACP(DD)	9413611116	ashishkg.doit@rajasthan.gov.in
2.7 Rajiv Gandhi Fintech Digital University:	Sh. Anil Kumar Singh, GGM(T)	9413387300	anilsingh.risl@rajasthan.gov.in
2.8 Rajiv Gandhi Institute of Advance Technology :	Sh. Anil Kumar Singh, GGM(T)	9413387300	anilsingh.risl@rajasthan.gov.in
2.9 Command and Control Center	Sh. Amit Sharma, M(T)	9413343504	amit.risl@rajasthan.gov.in
2.10 Wildlife Surveillance and Anti-Poaching System (WS&APS)	Ms. Sonia Chaturvedi, SA(JD)	9413387319	sonia@rajasthan.gov.in

Common Platform

Project	OIC Name and Designation	Mobile No.	E-mail
3.1 Raj-eSign	Sh. R.L. Solanki, AD	9414053106	rlsolanki@rajasthan.gov.in
3.2 e-Sanchar 3.0	Sh. Pawan Kumar Jangid, SA(JD)	9462778507	pkjangid.doit@rajasthan.gov.in
3.3 Rajasthan Single Sign-On (RajSSO)	Sh. Rajeev Gujral, SA(JD)	9829318018	rajeev.gujral@rajasthan.gov.in
3.4 Raj Evault	Sh. Pradeep Sharma, ACP(DD)	7014714205	pradeepks.doit@rajasthan.gov.in
3.5 RajPayment Platform	Sh. Yuvraj Gurjar , SA(JD)	9413206493	yuvrajsingh.doit@rajasthan.gov.in
3.6 RajUdyogmitra – MSME Act 2019	Sh. Rajeev Gujral, SeMT SPO	9829318018	rajeev.gujral@rajasthan.gov.in
3.7 RajNivesh	Sh. Rajeev Gujral, SeMT SPO	9829318018	rajeev.gujral@rajasthan.gov.in
3.8 Rajasthan Single Window Clearance System (SWCS)	Sh. Rajeev Gujral, SEMT-SPO	9829318018	rajeev.gujral@rajasthan.gov.in
3.9 e-Bazaar	Ms. Sonia Chaturvedi, SA(JD)	9413387319	sonia@rajasthan.gov.in
3.10 eBusiness Portal	Sh. Rajesh Saini, GM(T)	9413387304	rajeshsaini.risl@rajasthan.gov.in
3.11 Jankalyan	Sh. Rajesh Saini, GM(T)	9413387304	rajeshsaini.risl@rajasthan.gov.in
3.12 Rajdhara	Smt. Shweta Saxena, ACP(DD)	8107109511	shwetasaxena.doit@rajasthan.gov.in
3.13 3D City:	Sh. Deekap Raj, ACP(DD)	9828222283	deepakraj.doit@rajasthan.gov.in
3.14 Raj Mail	Sh. Dheeraj Gaur , SA(JD)	8955893990	dheerajgaur.doit@rajasthan.gov.in
3.15 Data Analytics and Big Data Cluster	Sh. Dheeraj Gaur , SA(JD)	8955893990	dheerajgaur.doit@rajasthan.gov.in

Office Automation

Project	OIC Name and Designation	Mobile No.	E-mail
4.1 RajKaj – An integrated e-office	Sh Vijay Prakash, SA(JD)	9462568030	vijayp.doit@rajasthan.gov.in
4.2 Raj ERP	Sh. Umesh Joshi, ACP(DD)	9694418180	umeshcj.doit@rajasthan.gov.in

Applications and Softwares

Project	OIC Name and Designation	Mobile No.	E-mail
5.1 RajCAD	Smt. Neelu Jain, SA(JD)	9413386193	neelu@rajasthan.gov.in
5.2 Right to Information (RTI Portal) 2.0	Ms. Sonia Chaturvedi, SA(JD)	9413387319	sonia@rajasthan.gov.in
5.3 Rajasthan Recruitment Portal	Smt. Munesh Lamba, ACP(DD)	9660844449	muneshlamba.doit@rajasthan.gov.in

Project	OIC Name and Designation	Mobile No.	E-mail
6.1 iStart	Sh. Tapan Kumar, SA(JD)	9413387307	tapan@rajasthan.gov.in

IT Initiatives in the fight against COVID -19	Sh. Tapan Kumar, SA(JD)	9413387307	tapan@rajasthan.gov.in

DoIT

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार

आईटी बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम
जयपुर-302005 (राजस्थान), भारत
फोन: 91(141) 2224855, 5153225